



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]
No. 78]नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 15, 2011/चैत्र 25, 1933
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 15, 2011/CHAITRA 25, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2011

(मध्यावधि समीक्षा)

विषय : चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एसिटोन पर लागू पाटनरोधी शुल्क से संबंधित मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत।

सं. 15/2/2011-डीजीएडी.—यतः 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् “पाटनरोधी नियम” कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् “प्राधिकारी” कहा गया है) ने दिनांक 4 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं. 14/4/2006-डीजीएडी द्वारा चीनी ताइपेई, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एसिटोन (जिसे एतदपश्चात् “संबद्ध वस्तु” कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए आंतिम परिणाम अधिसूचित किए थे।

2. और यतः दिनांक 11 मार्च, 2008 की सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 33/2008-सीमा-शुल्क द्वारा संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था।

3. और यतः प्राधिकारी को मै. फार्मोसा केमिकल एंड फाइबर कॉर्पोरेशन, चीनी ताइपेई से एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा प्राधिकारी से चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद

4. मूल जांच में विचाराधीन “उत्पाद एसिटोन” था। इस समीक्षा के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद समान है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई मूल जांच के अनुसार इस उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है-

“विचाराधीन उत्पाद “एसिटोन” है। एसिटोन एक कार्बनिक रसायन है जिसे डायमिथाइल कीटोन के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रयोग थोक घेषजों, कृषि रसायनों, रंगक सामग्री, कुछ चुनिंदा विस्फोटकों और अनुषंगी रसायनों के विनिर्माण में किया जाता है। एसिटोन सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के तहत उपशीर्ष संख्या 29141100 के अंतर्गत वर्गीकृत है।”

"यह एकल ग्रेड में उत्पादित होने वाला मूलभूत कार्बनिक रसायन है। यह एक रंगहीन द्रव है जिसकी सुगंध ईथर जैसी होती है। इसका इस्तेमाल अनेक कार्बनिक संश्लेषणों में विलायक अथवा मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग थोक धेखों, कृषि रसायनों, रंजक सामग्री, कुछ चुनिदा विस्फोटकों और अनुबंधी रसायनों के विनिर्माण में किया जाता है। आइसोफोरोन, डायसिटैन, एल्कोहल, मिथाइल मिथाक्राइलेट और बायशोफ्नॉल-ए के विनिर्माण में एसिटैन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग कुछ रबड़ रसायनों अथवा ऑक्सी एसिथाइलीन सेल्युलोज एसिटेट के विनिर्माण में किया जाता है।"

5. यह उत्पाद आईटीसीएचएस के सीमा-शुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 2914.11 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि उक्त सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

संबद्ध देश

6. मौजूदा समीक्षा जांच में शामिल देश चीनी ताइपेई है।

समीक्षा के आधार

7. आवेदक ने मध्यावधि समीक्षा के लिए अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए हैं:—

(क) कि मूल जांच की जांच अवधि की तुलना में इस जांच अवधि के दौरान मूलभूत कच्ची सामग्री (अर्थात् बैंजीन और प्रोपाइलिन) की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(ख) चीनी ताइपेई से निर्यात के मामले में मूल जांच की तुलना में भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। चीनी ताइपेई से अन्य देशों को हुए निर्यातों की निर्यात कीमत के संबंध में भी यही प्रवृत्ति लक्षित की गई है।

(ग) जांच की प्रस्तावित अवधि के दौरान आवेदक द्वारा नकारात्मक पाटन मार्जिन का दावा किया गया है।

(घ) अधिनियम में संशोधन के आधार पर सामान्य मूल्य के परिकलन की पद्धति में परिवर्तन हुआ है।

(ङ) मूल जांच की तुलना में भारत में घरेलू बिक्री कीमतों में भी उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

प्राधिकारी के मतानुसार परिस्थितियों में ऊपर उल्लिखित परिवर्तनों से मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत आवश्यक है।

जांच की शुरुआत

8. लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा को आवश्यक सिद्ध करने वाली परिवर्तित परिस्थितियों को दर्शाते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया सूचना को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का मत है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अनुसार आवेदन में उल्लिखित परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उचित है।

9. दिनांक 4-1-2008 की अधिसूचना संख्या 14/4/2006-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों की समीक्षा करने का निर्णय लेने के पश्चात् प्राधिकारी इस बात की जांच करने कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "एसिटोन" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण जारी रखना आवश्यक है और क्या शुल्क समाप्त किए जाने अथवा उसकी राशि में परिवर्तन करने या दोनों की स्थिति में क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है, के लिए पाटनरोधी नियमावली और अधिनियम के अनुसार एतद्वारा मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

प्रक्रिया

10. इस जांच से यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या पाटन की भरपाई के लिए पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण जारी रखना आवश्यक है और क्या शुल्क समाप्त किए जाने अथवा उसकी राशि में परिवर्तन करने या दोनों की स्थिति में क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है। जहाँ तक संबद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों का संबंध है, इस समीक्षा जांच में दिनांक 4 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं. 14/4/2006-डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

जांच की अवधि :

11. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्टूबर, 2009 से 30 सितम्बर, 2010 (12 माह) है। तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं जांच अवधि शामिल है।

सूचना प्रस्तुत करना

12. संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों नई दिल्ली में ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित के रूप में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उत्पादकों को निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:—

निर्दिष्ट प्राधिकारी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी)

उद्योग भवन

नई दिल्ली-110011

13. अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत अपने अनुरोध निर्धारित प्रयत्र में नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

14. मौजूदा समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जाए। यदि निर्धारित समयावधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

15. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सेटों—
(क) एक सेट (शीर्षक, विषयसूची, पृष्ठों की संख्या आदि सहित) गोपनीय चिह्नित हो, और (ख) दूसरा सेट (शीर्षक, विषयसूची, पृष्ठों की संख्या आदि सहित) अगोपनीय चिह्नित हो, में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में स्पष्ट रूप से “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” लिखा होना चाहिए।

16. ऐसे किसी चिह्न के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी। गोपनीय तथा अगोपनीय रूपांतर की दो-दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

17. गोपनीय मानी गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रस्तुत की झड़-सूचना के साथ-साथ इस आशय का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं किया जा सकता और/अथवा क्यों ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

18. अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होना चाहिए जिसमें उस सूचना जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है के आधार पर गोपनीय सूचना को सूचीबद्ध किया गया हो अथवा उसका स्थान रिकॉर्ड रखा गया हो/सारांश दिया गया हो। अगोपनीय सारांश में पर्याप्त व्यौरा दिया जाना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का समुचित अर्थ समझा जा सके। तथापि अपवादात्मक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह उल्लेख कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में सारांश न बनाए जा सकने के संतोषजनक कारणों का विवरण निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

19. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत या सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राथिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसी कोई सूचना जिसके साथ उसका सार्थक अगोपनीय रूपांतर अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में कारणों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न न हो, को रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के संबंध में अपनी संतुष्टि कर लेने और उसकी आवश्यकता स्वीकारने के बाद ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकार के बिना उसे किसी अन्य पक्ष के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर की सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग

22. ऐसे मामलों में जहां हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इंकार करते हैं अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं करते हैं अथवा जांच में अत्यधिक बाधा ढालते हैं तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2011

(Mid Term Review)

Subject : Initiation of Mid Term Review investigation in respect of the anti-dumping duties imposed on imports of “Accetone” originating in or exported from Chinese Taipei.

No. 15/2/2011-DGAD.—Whereas, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules), *vide* Notification No. 14/4/2006-DGAD, dated 4th January, 2008, the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive anti-dumping duty on import of Accetone (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from Chinese Taipei, European Union, Singapore, South Africa and U.S.A.

2. And whereas definitive anti-dumping duty was imposed on the subject goods *vide* Customs Notification No. 33/2008-Customs, dated 11th March, 2008.

3. And whereas an application has been received by the Authority from M/s. Formosa Chemical and Fibre Corporation, Chinese Taipei requesting the Authority to undertake a Mid Term Review of the anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from Chinese Taipei.

Product under consideration

4. The Product under consideration in the original investigation was Accetone. The Product under consideration remains the same for the purposes of this review. As per the original investigation carried out by the Designated Authority, the product has been defined as under :

“The product under consideration is “Accetone”. Acetone is organic chemical also known as Dimethyl Ketone and used in the manufacture of bulk pharmaceuticals, agro-chemicals, dye stuffs, certain explosives and downstream chemicals. Acetone is classified under Chapter 29 of Custom Tariff Act under the sub-heading 2914 11 00.”

“It is a basic organic chemical produced in single grade. It is a colourless liquid with an agreeable ether-like odour. It is used in numerous organic synthesis either as solvent or as an intermediate. It is used in manufacture of bulk pharmaceuticals, agro-chemicals, dyestuffs, certain explosives and downstream chemicals. Acetone is specifically used in manufacture of Isophorone, Diacetone, Alcohol, Methyl Methacrylate and Bisphenol A. Besides this, it is used in manufacture of certain rubber chemicals or Oxy Acetylene Cellulose Acetate.”

5. This product is classified under Customs Tariff heading No. 2914.11 of ITCHS. However, the said Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Subject country

6. The country involved in the present review investigation is Chinese Taipei.

Grounds for review

7. The Applicant has, *inter alia*, listed the following grounds for undertaking the mid-term review :

- (a) That basic Raw Materials (viz. Benzene and Propylene) prices have significantly increased during the period of investigation as compared to the POI of the original investigation.
- (b) There is significant increase in export price of subject goods to India as compared to the original investigation in respect of exports from Chinese Taipei. Same trend has been noticed in respect of export price to other countries from Chinese Taipei.
- (c) Negative Dumping Margin has been claimed by the applicant during the proposed period of investigation.
- (d) There is a change in methodology of computation of Normal Value based on amendment in the Act.
- (e) Domestic sales price in India has also shown significant increase as compared to the original investigation.

The Authority considers that changes in the circumstances as enunciated above necessitate initiation of a mid-term review.

Initiation

8. Having regard to the *prima facie* information provided by the applicant indicating the changed circumstances necessitating a review of the Anti-dumping measure in force, the Authority considers that a mid-term review of the Anti-dumping Duty is appropriate in view of the changed circumstances as mentioned in the Application, in terms of the Rule 23 of the AD Rules.

9. Having decided to review the Final Findings notified vide Notification No. 14/4/2006-DGAD dated 4th January, 2008, the Authority hereby initiates the mid-term review investigation in terms of the AD Rules and the Act, to review whether continued imposition of the duty concerning imports of 'Acetone' originating in or exported from the Chinese Taipei is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

Procedure

10. The investigation will determine whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury is likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. The review will cover all aspects of Notification No. 14/4/2006-DGAD dated 4th January 2008 so far as imports of the subject goods originating in or exported from the subject country are concerned.

Period of Investigation

11. The period of investigation for purposes of the present review is 1st October, 2009 to 30th September, 2010 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2007-08, 2008-09, 2009-10 and the POI.

Submission of Information

12. The known exporters in the subject country, the government of the subject country through Taipei Economic and Cultural Center in New Delhi, the importers and users in India known to be concerned and the Domestic producers are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the :

The Designated Authority,
 Ministry of Commerce and Industry,
 Department of Commerce,
 Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties (DGAD),
 Udyog Bhawan, New Delhi-110007

13. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below:

Time Limit

14. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned hereinabove not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

Submission of information on Confidential basis

15. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

16. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

17. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

18. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential

information may indicate that such information is not susceptible of summary, a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Designated Authority.

19. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary, form, it may disregard such information.

20. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Designated Authority. The Designated Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

21. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Use of 'facts available'

22. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

VIJAY LAXMI JOSHI, Designated Authority